

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग:

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2006

विषय : नगर पालिका विकास नगर सीमान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 के दोनों ओर फुटपाथ एवं डिवाइडर के निर्माण हेतु वर्ष-2006-07 में वित्तीय, प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका विकास नगर सीमान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 के दोनों ओर फुटपाथ एवं डिवाइडर के निर्माण हेतु वर्ष-2006-07 में रु०-497.80 लाख की लागत के आगणन के विपरीत टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु०-443.85 लाख (रुपये चार करोड़ तैंतालिस लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशि आपके द्वारा समस्त तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके चार समान किशतों में पूर्व स्वीकृत किशत का पूर्ण उपयोग करने के बाद आगामी किशत आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, अधीक्षण अभियंता रा०मा०वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून, को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 4- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के अधीक्षण अभियंता/ अधिशासी अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- 5- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परवेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी

आदेश
नियंत्रित
सचिव
शहरी विकास
विभाग

अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक

- 18- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2006-07 के आय व्ययक के अनुदान सं0-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-20 सहायक अनुदान/अनुदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 19- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-317/XXVII(2)/2006,दिनांक-14 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 2439/V-शा0वि0-06, तददिनांक।

- प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
 - 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
 - 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 4- निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी को गा0 मंत्रीजी के सूचनार्थ।
 - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 6- जिलाधिकारी, देहरादून।
 - 7- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, बडकोट।
 - 8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
 - 9- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
 - 10- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर।
 - 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अमरेन्द्र सिन्हा
(मायावती ठाकुरियाल)
अनुसंधान
शहरी विकास
उत्तरांचल शासन

अमरेन्द्र सिन्हा
(सं0के0जोशी)
अपर सचिव।

श्रीक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग:

विषय : नगर पालिका परिषद श्रीनगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यों हेतु वर्ष-2006-07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंधमें।

देहरादून: दिनांक-25 जुलाई, 2006

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से संलग्न सूची में उल्लिखित कार्य हेतु प्रस्तुत रु०-297.87 लाख की लागत के आगणन विपरीत टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु०-233.05 लाख (रुपये दो करोड़ तैंतीस लाख पांच हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 3- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- 6- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुरितका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मिलावट के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का

- प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा। कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 17- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 18- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०-316/XXVII(2)/2006, दिनांक-14 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं० 650(1)/V-श०वि०-06, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० नगर विकास मंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 6- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
- 7- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
- 8- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
- 9- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा
(नियामकी अधिकारी)
अनुमति
नगर विकास
उत्तरांचल शासन

आज्ञा से,

21.7.06
(एन०के०जी०सी०)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 650/v-श0वि0-06-77(सा0)/06 दिनांक 2 जुलाई, 2006 का संलग्नक

क्र०सं०	कार्य का नाम	आगणन लागत (रु० में)	की टी०.ए.सी.से (लाख अनुमोदित (लाख रु० में)
01	रामलीला मैदान श्रीनगर में सामुदायिक भवन/दुकानों का निर्माण।	166.74	105.86
02	नये बरा स्टैण्ड से निरंकारी सत्संग भवन तक सी०सी० टाईल सड़क, फुटपाथ, सुरक्षा रैलिंग, नाली एवं ह्यूम पाईप नाले का निर्माण कार्य।	62.50	60.75
03	वार्ड नं०-9 में अलंकनन्दा नदी के किनारे बहुपयोगी पार्क एवं एप्रोच सड़क का निर्माण।	39.17	38.17
04	वार्ड नं०-3 में अलंकनन्दा विहार में पशुबधशाला के नीचे नदी तक नाला निर्माण।	29.46	28.27
	कुलयोग	297.87	233.05

(रुपये दो करोड़ तैंतीस लाख पांच हजार मात्र)

राधा
(आयायती ठाकरियाल)
अनुसदिव
राहरी विकास
उत्तरांचल शासन

- कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- 7- योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा। यदि भूमि की उपलब्धता एक माह के भीतर सुनिश्चित नहीं होती है और कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - 8- यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
 - 9- कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, जम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई0ओ0 के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।
 - 10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किशतों में आहरण किया जायेगा। शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्राप्त करने के बाद ही आगामी किशत अवमुक्त की जायेगी।
 - 11- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किशतों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किशत तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
 - 12- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
 - 13- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यगजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
 - 14- विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशारी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
 - 15- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
 - 16- जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण ईकाई से आगणन की कुल लागत का 10

शासनादेश संख्या 24/39/V-श0वि0-06-208(सा0)/05-टी0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 2006
का संलग्नक

क्र०सं 0	कार्य का नाम	आगणन की लागत	टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित आगणन /स्वीकृत धनराशि
01	मार्ग के दोनों ओर नाली कवर एवं फुटपाथ का कार्य	177.70	155.40
02	मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य	274.97	246.55
03	मार्ग के मध्य डिवाइडर का कार्य	46.20	41.90
	कुल योग	497.80	443.85

मार्ग
(नियमित वार्षिक)
संग्रहित
नगर प्रकाश
एलएनए बाजार

(रुपये चार करोड़ तैंतालिस लाख पिचासी हजार मात्र)

- 6- निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 7- यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
- 8- कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा।
- 9- स्वीकृत कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भू-तल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, जिसकी प्रतिलिपि शासन को भी उपलब्ध करा दी जाय।
- 10- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके चार किशतों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किशत तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
- 11- आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशारी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 12- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- 13- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 14- विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशारी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
- 15- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- 16- कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
- 17- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता/अधिशारी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(नायबती ठेकरियाल)
अनुसन्धिव
गहरी विकास
उत्तरांचल शासन